मूल्य 1 रु.

वर्षः 10 - अंक : 197, मुंबई, बुधवार, 14 अक्टूबर, 2020 ■ RNI.NO. MAHHIN/2010/34146 ■ संपादकः दिलशाद एस. खान

दैनिक

मुंबई हलचल

भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त R

अब हर सच होगा उजागर

महबूबा को... हिरासत से आजादी

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती 14 महीने बाद रिहा

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को मंगलवार को हिरासत से रिहा कर दिया गया। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने इस बात की जानकारी दी। महबूबा को पिछले साल अगस्त में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर हिरासत में लिया गया था।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

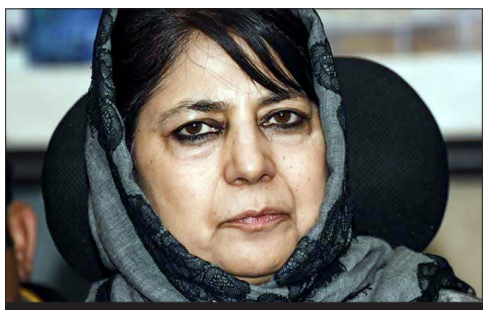

पिछले साल 370 हटाने पर हिरासत में लिया गया था

फारूक और उमर अब्दुल्ला रिहा हो चुके हैं

महबूबा जम्मू-कश्मीर की अकेली ऐसी बड़ी नेता थीं, जिन्हें अभी तक नजरबंद रखा गया था। उनके साथ ही हिरासत में लिए गए पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिहा किया जा चुका है। फारूक को 15 मार्च को रिहा किया गया था वहीं उमर को इसके 10 दिन बाद 25 मार्च को रिहा किया गया था।

'कोविड-19 से उत्पन्न हालात की समीक्षा के बाद धार्मिक स्थलों खोलने का फैसला होगा'

(समाचार पृष्ठ 3 पर)

'साम्प्रदायिक टिप्पणी' मामले में अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस का नोटिस

मुंबई। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को पालघर में साधुओं की भीड़ द्वारा हत्या और अप्रैल में बांद्रा स्टेशन के पास प्रवासी कामगारों की भीड़ पर प्रसारित कार्यक्रम में कथित तौर पर साम्प्रदायिक टिप्पणी करने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अर्नब गोस्वामी को सीआरपीसी की धारा-108 के तहत नोटिस जारी किया गया है और पूछा गया है कि क्यों न उनसे अच्छे व्यवहार संबंधी मुचलका जमा कराया जाए।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

फैक्ट्री में धमाके से दहला अलीगढ़

मलबे में दबने से 3 की मौत, कई घायल

संवाददाता

अलीगढ़। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ शहर मंगलवार को एक तेज धमाके से दहल उठा। दरअसल, शहर के एक मकान में प्लास्टिक के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में रखा एलपीजी सिलेंडर तेज आवाज के साथ फट गया। जिसकी वजह से वो मकान भरभरा कर नीचे गिर गया। उसके मलबे में दबने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह धमाका देहली गेट थाना क्षेत्र के खटीकान मोहल्ले में हुआ।

(शेष पृष्ठ 3 पर)

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

हमारी बात

ताकि मांग बढ़े

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिन सुविधाओं की घोषणा की, वह लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में नया जोश भरने की एक और कवायद है। ये व्यावहारिक कदम हैं, और इनसे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग के बढ़ने की उम्मीद बांधी जा सकती है। इन सुविधाओं के तहत तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को दस हजार रुपये की करमुक्त राशि अग्रिम भुगतान के रूप में दी जाएगी और कर्मचारी इसे 31 मार्च तक किसी भी त्योहार में खर्च कर सकेंगे। उन्हें दस किस्तों में इसे लौटाने की सुविधा होगी। इसी तरह, 'एलटीसी कैश वाउचर स्कीम' में कर्मचारी 'रिइंबर्समेंट' की बजाय सीधे नकदी का दावा कर सकेंगे और इस राशि का इस्तेमाल भी उन्हें 31 मार्च से पूर्व कर लेना होगा। अपने कर्मचारियों के अलावा केंद्र ने राज्यों को भी पूंजीगत व्यय के लिए 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज देने का एलान किया है। राज्य 31 मार्च तक अपनी नई-पुरानी योजनाओं पर इसे खर्च कर सकेंगे और उनके पास अगले 50 वर्षों में इसे चुकाने की सहूलियत होगी। सरकार का आकलन है, जो तर्कसंगत भी है कि इन कदमों से बड़ी मांग पैदा होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम देशी-विदेशी वित्तीय व रेटिंग संस्थाओं के जो आकलन हैं, वे सरकार की पेशानी पर बल डालने के लिए काफी हैं। हालांकि, अनलॉक की प्रक्रिया के आगे बढ़ने के बाद बाजार में स्थितियां कुछ सुधरी हैं, खुद वित्त मंत्री ने भी आपूर्ति शृंखला में सुधार की स्थिति पर संतोष जताया है। लेकिन यह एक सर्वमान्य बात है कि बाजार में मांग बढ़ाए बिना अर्थव्यवस्था की पटरी पर वापसी मुमकिन नहीं है। और मांग बढे, इसके लिए जरूरी है कि उपभोक्ताओं के जेहन से महामारी से जुड़ी आशंकाएं तिरोहित हों और वे खुलकर खर्च करने की स्थिति में आएं। लॉकडाउन ने मध्यवर्ग को किफायती खर्च के लिए बाध्य किया है और जब तक कोविड-19 से जुड़ी स्थितियां सामान्य के करीब नहीं पहुंचेंगी, सामाजिकता नहीं बढ़ेगी, तब तक उनका पूर्व स्थिति में लौटना कठिन है। ऐसे में, केंद्रीय कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं की अहमियत समझी जा सकती है। दुनिया भर के कई अर्थशास्त्री और विपक्ष के नेता केंद्र सरकार से अपील करते रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए उसे गरीबों की जेब में कुछ अरसे तक पैसे डालने पड़ेंगे, ताकि बाजार में मांग की स्थिति सुधरे। उनका जोर खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऊर्जा पैदा करने पर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने की इसकी क्षमता असंदिग्ध है। कोरोना-काल ने तो इसके प्रामाणिक आधार भी मुहैया कराए हैं। जब सभी क्षेत्रों की विकास दर जमीन पर लेट रही थी, तब कृषि क्षेत्र देश को उम्मीद की रोशनी दिखा रहा था। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ठोस क्षमताओं को देखते हुए ही मनरेगा का बजटीय आबंटन बढ़ाया है। भारत में त्योहार अर्थव्यवस्था को मजबूत संबल देते हैं। यही वक्त होता है, जब खासतौर से ग्रामीण लोग दैनिक जरूरतों के आगे की खरीदारी करते हैं। विशेष रूप से दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, ईद, गुरुपर्व और क्रिसमस हमारी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देते आए हैं। कोरोना ने इस साल के त्योहारों का रंग फीका कर दिया है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के उडे. रंग इन्हीं की बदौलत सुर्खरू भी होंगे। सरकार को कुछ और राहतें असंगठित क्षेत्रों पर भी बरसानी होंगी।

आखिर टीवी रेटिंग प्वॉइंट कैसे काम करता है और इसमें कितनी विसंगतियां हैं

आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल। एक न्यूज चैनल पर यह दावा वर्षों से आप रोज दर्जनों बार सुनते होंगे। सुनते भी होंगे और यकीन भी कर लेते होंगे कि वास्तव में जो चैनल खुद को न्यूज की दुनिया का नंबर वन बता रहा है वही खबरों की दुनिया का असली बादशाह है। और जो इन दावों पर यकीन नहीं करते उनको यकीन दिलाने के लिए यह चैनल, खबरों के बीच-बीच में टीवी रेटिंग प्वॉइंट के आंकड़े दिखाता रहता है। इतने पर भी संतुष्टि कहां! इसलिए अक्सर समाचार पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापन देकर टेलीविजन रेटिंग प्वॉइंट के तुलनात्मक आंकड़े छापे जाते हैं और इस तरह अपनी सफलता के डंके पीटे जाते हैं। यह दावा है कि बीते लगभग डेढ़ दशकों से एक ही न्यूज चैनल नंबर वन की कुर्सी पर काबिज है। इन डेढ़ दशकों में दर्जनों न्यूज चैनल आए (कुछ चले भी गए) जिन्होंने बहुत अच्छा किया वो भी खींचतान कर दूसरे पायदान पर पहुंचे और उससे ही संतुष्ट होकर रह गए। जब बादशाह की बादशाहत को कोई चुनौती नहीं दे सका तो प्रतिद्वंद्वी चैनलों ने एक नया रास्ता निकाला, किसी ने दावा करना शुरू किया कि वह देशभर में नहीं, पर देश के चार महानगरों में नंबर वन है, तो किसी ने दावा किया कि वह शाम सात से नौ बजे के प्राइम टाइम स्लॉट में नंबर वन है। तो इस तरह बादशाह को किसी ने चुनौती नहीं दी, पर अपना-अपना कारोबार भी चलता रहे, इसका उन लोगों ने प्रबंध कर लिया और इस तरह टीवी रेटिंग प्वॉइंट यानी टीआरपी का खेल बरसों तक चलता रहा। किसी ने सवाल नहीं किए कि नंबर वन, नंबर टू से लेकर फिसड्डी चैनल का खिताब देने वाला टीआरपी सिस्टम कितना विश्वसनीय और कितना चाक-चौबंद है। जिन लोगों ने सवाल उठाए, उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया गया।

करीब एक दशक पहले एक गोष्ठी में टीआरपी की व्यवस्था को फर्जी बताते हुए मैंने उसका विरोध किया था। तब एक न्यूज चैनल के वरिष्ठ संपादक ने पलटवार करते हुए कहा था कि चूंकि मैं डीडी न्यूज में हूं, जिसे टीआरपी नहीं मिलती, इसलिए विरोध कर रहा हूं। हालांकि आज उन्हें जब टीआरपी के खिलाफ ट्वीट करते हुए देखता हूं, तो बड़ी हैरानी होती है। दरअसल तब वह संपादक निजी चैनलों के सिस्टम का हिस्सा थे, परंतु आज वह स्वयं ही इस सिस्टम से बाहर हैं। बहरहाल, बीते एक-दो सप्ताह में अचानक से इस संदर्भ में बहुत कुछ बदल गया है। पिछले साल फरवरी में लांच हुए एक न्यूज चैनल ने बीते डेढ़ दशक से बादशाह रहे चैनल का नंबर वन का ताज छीन लिया। इससे टीवी न्यूज की दुनिया में नया बवंडर पैदा हुआ। टीआरपी की इस लड़ाई में बहुत कुछ हो रहा था, कुछ सामने-सामने तो कुछ पर्दे के पीछे। और ये पर्दा उठाया मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने, जब अचानक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीआरपी के खेल में बेईमानी को उजागर किया। मुंबई पुलिस कमिश्नर के आरोपों ने एक न्यूज चैनल के साथ-साथ टीआरपी की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। हालांकि उसके बाद संबंधित न्यूज चैनल ने इस मामले से जुड़े कुछ नए तथ्य उजागर किए और अपनी सफाई के साथ उसने अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धी पर धांधली के आरोप जड़ दिए। इस पलटवार से अब खुद पुलिस कमिश्नर की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में आ गई है। पर इससे टीआरपी में हेर-फेर का कलंक तो नहीं धुला, अलबत्ता पूरा मामला और जटिल हो गया है और सभी पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर आरोपों की बौछार भी हो रही है। ये सब अभी चलता रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ नंबर वन के ताज की लड़ाई नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये के विज्ञापन बाजार पर कब्जे की जंग है। कोई नहीं जानता कि इस जंग का अंजाम क्या होगा, पर बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मंथन से टीआरपी व्यवस्था स्वच्छता अभियान की तरफ कूच कर सकेगी?

आम लोगों से लेकर मीडिया जगत तक का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि टीआरपी के कारण न्यूज चैनलों के कंटेंट के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। टीआरपी बटोरने की होड़ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। निजी टीवी चैनलों में काम करने वाले संपादकों-पत्रकारों पर टीआरपी का चाबुक हमेशा लटका रहता है। हर गुरुवार को टीआरपी के आंकड़े जारी किए जाते हैं और उस दिन संपादक डरे सहमे रहते हैं कि पता नहीं उनका परिणाम क्या आएगा! परिणाम खराब होने की सजा के तौर पर कई बार प्रोग्राम-एंकर बदले तक जाते हैं। इन तमाम कारणों से हर दो-चार साल में टीवी न्यूज चैनलों को टीआरपी के शिकंजे से आजाद कराने की मांग उठती रही है।

पंजाब में सियासी कोलाहल में दबी कृषि माहिरों की आवाज

भारत के सबसे लंबे राजमार्ग (एनएच-44) पर होशियारपुर व जालंधर जिलों की सीमा पर स्थित है गांव जहूरा। वैसे तो यह गांव पंजाब के 13 हजार अन्य गांवों जैसा ही है, पर आज जब पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों पर चर्चा छिड़ी है तो ऐसे में इस गांव का जिक्र अत्यंत जरूरी और सामयिक है। यह देशभर में एकमात्र वह गांव है, जहां पेप्सिको जैसी मल्टीनेशनल कंपनी ने भारत प्रवेश की आज्ञा के बाद टमाटर से पेस्ट बनाने वाला देश का सबसे पहला प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया था।

इस प्लांट के शुरू होने से लेकर अब तक के सफर की कहानी में सिमटा है इन नए कृषि कानूनों की अहमियत और जरूरत का वह सार जिसे आज विपक्षी दलों समेत तमाम किसान संगठन पूरी तरह नजरअंदाज कर विरोध में खड़े हैं। वर्ष 1989 में प्लांट लगते ही यहां के हजारों किसानों ने कंपनी के साथ किए अनुबंध के तहत उसके द्वारा दी गई टमाटर की उन्नत किस्मों के बीजों का प्रयोग किया। बाजार में कीमत कंपनी अनुबंध के तहत तय की गई राशि से चार गुना ज्यादा क्या मिली, उत्साही किसानों ने टमाटर प्लांट को देने की जगह बाजार में बेच दिया। जब फसल का तय मौसम आया तो पूरे राज्य में टमाटर की पैदावार इतनी हुई कि एक पखवाड़े में ही टमाटर के

भाव कंपनी द्वारा निर्धारित रकम से भी सात गुना कम हो गए। बाजार छोड़ किसानों ने पुनः फैक्ट्री का रुख किया। प्लांट मैनेजमेंट ने फसल तो उठाई, लेकिन किसानों के साथ संबंधों में खटास पैदा हो गई। साल दर साल यही सब दोहराया जाने लगा और अंततः प्लांट बंद कर दिया गया।

इस घटनाक्रम को याद करते हुए देश के प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री पद्म भूषण सरदारा सिंह जौहल मानते हैं कि पूरे प्रकरण में अगर किसी का नुकसान हुआ तो इलाके के किसानों का और ऐसा इसलिए, क्योंकि उस समय किसानों के हित बचाने के लिए काट्रैक्ट फाङ्समग कानून जैसा कोई प्रावधान ही नहीं था। अगर होता तो आज जहूरा गांव के साथ-साथ निकटवर्ती जिलों के टमाटर उत्पादकों की स्थिति कुछ अलग होती। सीधे-सीधे कहें तो किसानों के नाम पर जारी इस जंग में शामिल तमाम किसान संगठनों और राजनीतिक दलों को सड़कों और रेलवे ट्रैक पर आने से पहले जहूरा गांव की इस कहानी और घटनाक्रम को समझने की सख्त जरूरत है।

अगर इन नए कानूनों में दर्ज प्रावधानों को देखें तो हर व्यक्ति के दिमाग में यह सवाल कौंधता है कि इसमें गलत क्या है अगर नया कानून किसान को यह कानूनी हक प्रदान करता है कि वह किसी भी व्यक्ति अथवा कंपनी से काट्रैक्ट फाङ्समग के तहत फसल बोने के पहले ही उसका दाम स्वयं तय कर सकता है। यही नहीं, उस करार को एकतरफा खत्म करने का अधिकार भी केवल किसान के पास होगा। दरअसल राजनीतिक खेल में आम किसान हमेशा से ही राजनीति का मोहरा बनते रहे हैं। अनाज की भारी जरूरत के चलते तत्कालीन केंद्र सरकारों ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत गैर सरकारी खरीदारों को मंडियों से बाहर का रास्ता इसलिए दिखा दिया था, ताकि कोई भी किसान को सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक कीमत देकर अनाज न खरीद सके। न सिर्फ अनाज के भंडारण पर रोक लगा दी गई, बल्कि अनाज को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाकर बेचने पर ऐसी पाबंदी लगी कि मंडियों में किसान केवल सरकार द्वारा तय रेट पर ही फसल बेचने को मजबूर हो गया।

दैनिक
मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

'कोविड-19 से उत्पन्न हालात की समीक्षा के बाद धार्मिक स्थलों खोलने का फैसला होगा'

संवाददाता

मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल बी एस कोश्यारी को सूचित किया है कि राज्य में कोविड-19 संबंधी हालात की पूरी समीक्षा के बाद धार्मिक स्थलों को पुनः खोलने का फैसला किया जाएगा। ठाकरे ने कोश्यारी के सोमवार को लिखे पत्र के जवाब में मंगलवार को पत्र लिखकर कहा कि राज्य सरकार इन स्थलों को पुनः खोलने के उनके अनुरोध पर विचार करेगी। कोश्यारी ने अपने पत्र में कहा था कि उनसे तीन प्रतिनिधिमंडलों ने धार्मिक स्थलों को पुनः खोले जाने की मांग की है। ठाकरे ने अपने जवाब में कहा कि यह संयोग है कि कोश्यारी ने जिन तीन पत्रों का जिक्र किया है, वे भाजपा पदाधिकारियों और समर्थकों

के हैं। कोश्यारी आरएसएस से जुड़े रहे हैं और भाजपा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा था, क्या आप अचानक धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं? इसके जवाब में ठाकरे ने सवाल किया कि क्या कोश्यारी के लिए हिंदुत्व का मतलब केवल धार्मिक स्थलों को पुनः खोलने से है और क्या उन्हें नहीं खोलने का मतलब धर्मनिरपेक्ष होना है। ठाकरे ने कहा, क्या धर्मनिरपेक्षता संविधान का अहम हिस्सा नहीं है, जिसके नाम पर आपने राज्यपाल बनते समय शपथ ग्रहण की थी। उन्होंने कहा, लोगों की भावनाओं और आस्थाओं को ध्यान में रखने के साथ साथ, उनके जीवन की रक्षा करना भी अहम है। लॉकडाउन अचानक लागू करना और समाप्त करना सही नहीं है।

अल्पसंख्यक विद्यार्थियों कह छात्रवृत्ति 2,000 से बढ़ाकर 4,000 किया

मुंबई। उच्च सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार उस समुदाय के छात्रों को आर्थिक मदद देती है। परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों को 2,000 रुपये प्रति महीना देती है, जिसे बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति माह किया जा रहा है। इस रकम को बढ़ाने के बाबत अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने बताया कि इसी तरह की स्कीम उच्च शिक्षा विभाग चलाता है, उसने पहले ही मदद की रकम 2,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दी है। अब यूपीएससी की

तैयारी में लगे छात्रों की रकम में बढ़ोतरी की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, क्रिश्चन, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ज्यू समाज के लोग आते हैं। इन समुदाय के लोगों का सरकारी सेवाओं में संख्या बढ़ाई जा सके, इसके लिए केंद्रीय लोकसेवा आयोग के (यूपीएससी) स्पर्धा परीक्षा की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक समाज के चयनित, होनहार छात्रों को इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य प्रशासकीय संस्था के मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर और संभाजीनगर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में प्रति केंद्र 10 विद्यार्थियों को यह प्रशिक्षण दिया जाता है। अल्पसंख्यक समाज के छात्रों के विद्यावेतन में भी वृद्धि के बाबत मंत्री मलिक बताया कि विद्यावेतन की यह बढ़ोत्तरी 2020-21 इस शैक्षणिक वर्ष से लागू की जा रही है।

दादी पर था जादू-टोना करने का शक, कर दी हत्या

पालघर। विक्रमगढ़ पुलिस स्टेशन क्षेत्र के यशवंत नगर इलाके में रविवार दोपहर जादू-टोना के शक में एक पोते ने अपनी दादी की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार, यशवंत नगर निवासी सोनी जानू दांगटे (62) अपने परिवार के साथ रहती थी। पिछले कुछ महीनों से उसका पोता कैलाश सखाराम दांगटे (24) बीमार था। उसे शक हुआ कि उसकी दादी जादू-टोना करके उसे बीमार कर रही है। इसी बात को लेकर वह दादी से हमेशा झगड़ा करता रहता था। रविवार दोपहर 12 बजे उसका दादी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने कुल्हाड़ी से दादी की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद वह जंगल में भाग गया। पुलिस की टीम उसे खोज रही है।

बिहार के पप्पू यादव समेत कई स्थानीय दल हमारे संपर्क में हैं: संजय राउत

मुंबई। बिहार चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो गई है। महाराष्ट्र में सत्ता के सिंहासन पर बैठी शिवसेना का कहना है कि पार्टी 40-50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि फिलहाल पार्टी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है लेकिन बिहार के बड़े नेता पप्पू यादव समेत कई क्षेत्रीय पार्टियां हमारे साथ लगातार संपर्क में हैं। संजय राउत ने बताया कि बिहार में शिवसेना फिलहाल 40 से 50 सीटों पर

चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जहां तक बात एनसीपी के साथ या फिर किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन की बात है तो अभी इस विषय पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अगले हफ्ते बिहार जाने के बाद में ही इस विषय पर अन्य राजनीतिक दलों से चर्चा करने के बाद फैसला किया जाएगा। शिवसेना ने बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। शिवसेना की तरफ से जो लिस्ट चुनाव आयोग को भेजी गई है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

महबूबा को हिरासत से आजादी

महबूबा एक साल, दो महीने और 9 दिन बाद हिरासत से रिहा हुई हैं यानी कुल 436 दिन बाद। महबूबा को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से एक दिन पहले 4 अगस्त की रात को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद से ही वे नजरबंद थीं। 6 फरवरी को महबूबा की हिरासत की अवधि समाप्त होने से पहले ही उन पर पब्लिक सेक्युरिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद उनकी नजरबंदी की अवधि बढ़ गई। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 में जम्मू-कश्मीर में लागू कर दिया गया था। इसके तहत किसी को भी बिना ट्रायल के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। पहले तो यह कानून लकड़ी की तस्करी करने वालों के खिलाफ बना था, लेकिन धीरे-धीरे इसका इस्तेमाल अन्य आपराधिक मामलों में भी होने लगा। खास इस्तेमाल तब किया गया, जब 2010 में जम्मू-कश्मीर में कई महीनों तक हालात खराब रहे। आठ महीने में चार बार महबूबा को नजरबंद रखने का स्थान बदला गया था। सबसे पहले उन्हें श्रीनगर के हरि निवास गेस्ट हाउस में रखा गया था। दूसरी बार उन्हें चश्मा शाही इलाके में पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस भेज दिया गया था। इसके बाद से उन्हें श्रीनगर के ही ट्रांसपोर्ट यार्ड के सरकारी क्वार्टर में रखा गया था। चौथी बार उन्हें अस्थाई जेल से किसी दूसरे स्थान पर भेजा गया।

फैक्ट्री में धमाके से दहला अलीगढ़

स्थानीय लोगों ने इस भीषण धमाके के बारे में बताया कि तेज धमाके की आवाज को सुनकर सब लोग मौके पर पहुंचे। सबने देखा कि वहां पर 5 घर टूट चुके हैं। वहां बच्चों के लिए प्लास्टिक के खिलौने बनाए जाते हैं। घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि वो मकान सुरेंद्र सिंह का है। सिलेंडर के धमाके से मकान धराशायी हो गया। मौके पर फायर टीम के साथ ही स्थानीय लोग भी पहुंचे। जो राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। मौके से 8 से 9 लोगों को निकालकर अस्पताल भिजवाया गया। जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी सभी लोगों का उपचार चल रहा है।

'साम्प्रदायिक टिप्पणी' मामले में अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस का नोटिस

अधिकारी ने बताया कि गोस्वामी को वर्ली डिवीजन के विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट और सहायक पुलिस आयुक्त के समक्ष शुक्रवार को शाम चार बजे उपस्थित होने को कहा गया है। नोटिस के मुताबिक 21 अप्रैल को गोस्वामी ने 'पूछता है भारत' कार्यक्रम में पालघर में दो साधुओं और उनके चालक की भीड़ द्वारा हत्या किए जाने पर बहस कराई थी और कथित तौर पर सवाल किया था कि हिंदू होना और भगवा पहनना अपराध है और क्या वे गैर हिंदू होते तो लोग ऐसे ही चुप रहते। अधिकारी ने बताया कि गोस्वामी से एक जमानतदार के साथ एक साल के लिए 10 लाख रुपये का मुचलका लिया जा सकता है जो उनके व्यवहार को नियंत्रित करे।

इकोनामी को एक और डोज

सरकारी कर्मियों को LTC के एवज में नकद वाउचर, फेस्टिवल एडवांस मिलेंगे ₹10,000

■ नई दिल्ली (संवाददाता)। सरकार ने त्योहारी सीजन में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए सोमवार को कई उपायों का ऐलान किया। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में नकद वाउचर और केंद्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को 10,000 रुपए का विशेष त्योहार अग्रिम (फेस्टिवल एडवांस) दिया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरकार अपने कर्मचारियों को एलटीसी के एवज में आयकर मुक्त नकद वाउचर देगी। कर्मचारी इन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर जीएसटी की दर 12 फीसद या अधिक है। इस शर्त का मतलब यह है कि कर्मचारी इस वाउचर का इस्तेमाल खाद्य उत्पाद खरीदने के लिए नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है। इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है। सीतारमण ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने उन्हें नकद वाउचर देने का फैसला किया है। इसे 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसई) और बैंक भी अपने कर्मचारियों को एलटीसी के स्थान पर नकदी देंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहार अग्रिम के रूप में 10,000 रुप देने की घोषणा की है। सीतारमण ने कहा कि इन दो उपायों से 28,000 करोड़ रुपए की उपभोक्ता मांग पैदा होने की संभावना है।

सरकार ने इस साल मई में 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। अब सरकार त्योहारी सीजन के दौरान मांग को प्रोत्साहन देने के कदम उठा रही है। आमतौर पर त्योहारी सीजन में लोग अधिक खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किए जाने वाले उपायों से आम नागरिक पर वोझ नहीं पड़ना चाहिए और न ही इससे भविष्य की मुद्रास्फीति प्रभावित होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार का कर्ज भी ऐसी दिशा में अग्रसर नहीं होना चाहिए जो टिक नहीं सकता हो। सीतारमण ने कहा, 'आज का समाधान कल की समस्या नहीं बनना चाहिए।'

■ मांग बढ़ाने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम

■ अर्थव्यवस्था को मार्च, 2021 तक मिलेगा कुल 73,000 करोड़ का प्रोत्साहन

कोरोना का अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हुआ हैं। प्रोत्साहन के बावजूद अब भी उपभोक्ता मांग कम बनी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे पैकेज तैयार किए गए हैं जिससे उपभोक्ता मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसका महंगाई पर भी असर नहीं होगा

- निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री

राज्यों को 12,000 करोड़ का मिलेगा ब्याजमुक्त कर्ज

नई दिल्ली (संवाददाता)। कोरोना वायरस महामारी के कारण केंद्र की ओर से जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान करने में असमर्थता जाहिर करने पर राज्य कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यों को 50 साल के लिए 12,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यह ब्याज मुक्त ऋण पूंजीगत व्यय के लिए दिया जा रहा है।

हाथरस कांड: सरकार ने हाईकोर्ट में रखा पक्ष

कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में शवदाह के लिए दिशा-निर्देश बनाये सरकार

लखनऊ (संवाददाता)। हाथरस कांड को लेकर यूपी सरकार ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अपना पक्ष रखा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन ने रात में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार कराया। इस मामले में राज्य सरकार की नीयत पूरी तरह साफ थी। दुर्भावनापूर्ण कोई निर्णय नहीं लिया गया। कोर्ट ने सुनवाई के वाद चैंबर में आदेश लिखने का फैसला किया। अगली सुनवाई दो नवम्बर को होगी।

लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को दिन में 2.15 वजे से हाथरस के वूलगढ़ी गांव में मृत दलित युवती के साथ कथित दुष्कर्म, मारपीट तथा प्रशासन द्वारा पीड़िता का रातोंरात अंतिम संस्कार कराने के मुद्दे पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई दो घंटे चली। विदित हो कि गत 14 सितम्बर को हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वयं संज्ञान लिया था, जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने अफसरों को तलव किया था। इससे पहले सोमवार को कड़ी सुरक्षा में मृतका के माता-पिता, भाई समेत पांच सदस्यों को हाईकोर्ट लाया गया। वहीं, खुद को पीड़ित परिवार का वकील वताते हुए अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने वताया कि कोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले को यूपी के वाहर किसी राज्य में ट्रांसफर किया जाये। जांच होने तक सभी तथ्य गोपनीय रखें और परिवार को सुरक्षा भी मिले। कोर्ट में पीड़ित परिवार के साथ ही राज्य सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, डीजीपी, हाथरस के डीएम व एसपी पेश हुए। परिवार की विना मर्जी के अंतिम संस्कार के सवाल पर हाथरस के डीएम व एसपी ने कहा कि कानून-व्यवस्था के मद्देनजर यह फैसला किया गया। इसके लिए राज्य सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिये थे।

सीनियर वकील जेएन माथुर ने कहा कि कोर्ट ने एक अक्टूबर को इस प्रकरण का संज्ञान लिया था। कोर्ट ने सोमवार को यह भी कहा कि राज्य सरकार को हाथरस मामले में इस तरह की परिस्थितियों में शवों के दाह संस्कार के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना होगा। अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही ने कोर्ट में राज्य के राज्य प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व किया। कोर्ट में पीड़ित परिवार के सभी पांच लोगों ने अपना-अपना पक्ष रखा। इसके वाद कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव गृह, एडीजी लॉ एंड आर्डर और डीएम हाथरस से भी सवाल किया और जानकारी ली। पीड़ित पक्ष की वकील सीमा कुशवाहा ने हाथरस पुलिस-प्रशासन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परिवार ने कहा है कि पुलिस ने शुरुआत से ही सही जांच नहीं की। हमें परेशान किया।

अगली सुनवाई 2 को

■ लखनऊ बेंच ने दर्ज किए पीड़िता के परिजनों, शीर्ष अधिकारियों व हाथरस के डीएम-एसपी के बयान

कानून-व्यवस्था वनाये रखने को रात में करायी अंत्येष्टि

लखनऊ (संवाददाता)। हाथरस मामले की इलाहावाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई के दौरान हाथरस के जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कहा कि कानून-व्यवस्था वनाये रखने के लिए जिला प्रशासन ने पीड़िता के शव का रात में अन्तिम संस्कार कराया।

पश्चिम बंगाल में हवा से फैल रहा है कोविड-19, दुर्गा पूजा में नियमों का करें पालनः ममता

कोलकाता। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारी जारी है। इस बीच भीड़ की वजह से कोविड-19 के बढ़ने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के फैलने को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगी कि वो घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहनें, क्योंकि ये काफी फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी परिवार में एक कोरोना संक्रमित शख्स की पहचान होती है तो खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। कोरोना संक्रमण अब कम्युनिटी स्तर पर फैल चुका है, इसलिए अगर कोई एक संक्रमित हो रहा है तो आठ अन्य लोग भी कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं। खासकर उनके परिवार के सदस्य ही संक्रमित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जिनसे पता लगता है कि कोरोना अब हवा के जरिए भी फैल रहा है। मैं लोगों को बाहर जाने से नहीं रोक सकती हूं। मैं जानती हूं कि अभी दुर्गा पूजा का समय है। इसलिए लोग बाहर निकलेंगे। लेकिन आप सबसे अनुरोध करूंगी कि खरीदारी के लिए बाहर ना निकलें। पूजा के लिए जब भी पंडाल में जाएं तो मास्क जरूर पहनें।

कोमल ठाकुर का बचपन से डांसर बनने का सपना हुआ पूरा

कोमल ठाकुर ने कहा कि अनाथ आश्रम द्वारा बूढ़े, अनाथ, अंध, अंपग बालकों की सेवा करने का है सपना

कोमल ठाकुर का बचपन से डांसर बनने का सपना पूरा हो गया है, उन्होने मुंबई सिनेमागृह में बहुत काम किया है। उन्होने नथक, डांसर, अभिनय, डान्स, एक्टिंग में बहुत काम किया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर उनके चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। मुंबई में रहकर कोमल ठाकुर का अभिनेत्री बनने का सपना है। यह सपना पूरा होने के बाद वह समाज सेवा करने वाली है। कोमल ठाकुर अनाथ आश्रम द्वारा बूढो, अनाथ, अंध, अंपग इनकी सेवा करना चाहती हैं। उन्होंने अध्ययन बी. कॉम तक किया है। कोमल ठाकुर अच्छी अभिनय के साथ-साथ अच्छी डांस भी करती है, आने वाले समय में उनका सपना पूरा हो यही शुभकामनाएं है।

भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल जल्दः स्वास्थ्य मंत्रालय

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की महामारी के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल जल्द शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल भी तीसरे चरण में है। इसके नतीजे नवंबर से दिसंबर तक आ जाने की उम्मीद है। वैक्सीन की खरीद के लिए धन से जुड़े सवाल पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि वैक्सीन बनाने वालों को प्री-क्लिनिकल ट्रायल में सहायता के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। सिंगल डोज और डबल डोज टीके अभी विकसित हो रहे हैं। उन्होंने कोरोना से हुई मौतों की चर्चा करते हुए कहा कि इनमें से 10 फीसदी 26 से 44 साल के आयु वर्ग के युवा हैं। इसे लेकर चिंता जताते हुए राजेश भूषण ने कहा कि 35 फीसदी 45 से 60 साल आयु वर्ग के लोग हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कहा कि अब तक कोरोना के 62 लाख मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में पॉजिटिविटी रेट 8.07 फीसदी है। देश में इस समय कोरोना के 9 लाख से कम एक्टिव केस हैं। उन्होंने दावा किया कि टेस्टिंग बढ़ी है और पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। एक दिन में 11 लाख 36 हजार टेस्ट किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टेस्टिंग, देश के प्रति 10 लाख पर टेस्टिंग के औसत से अधिक है। इन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट भी राष्ट्रीय औसत से नीचे है। प्रतिदिन नए मामलों के लिहाज से केरल देश में तीसरे नंबर पर है। कुछ सप्ताह पहले तक केरल शीर्ष 10 राज्यों में भी नहीं था। इस सूची में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष दो राज्य हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि मंत्रालय लगातार इन राज्यों के संपर्क में है। एनसीडीसी के अनुमान का जिक्र करते हुए डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि सर्दियों में दिल्ली में रोजाना 15 हजार नए मामले सामने आने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इसके लिहाज से तैयारी की गई है।

हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि इतने केस आए ही। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के डीजी बलराम भार्गव ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में दोबारा इंफेक्शन के दो दर्जन मामले सामने आए हैं। हमारे यहां भी कुछ लोग दोबारा संक्रमित हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोबारा संक्रमण का डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ भी डिसाइड नहीं कर रहा। 100 दिन बाद वायरस दोबारा अपनी चपेट में ले ले रहा। भार्गव ने कहा कि जो लोग ठीक हो चुके हैं, करीब 4 महीने तक एंटीबॉडी रहती है।

दिशा सलियान की मौत का रहस्य बरकरार, सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुआ कोई वकील

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सलियान की मौत का रहस्य बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की वचुंअल सुनवाई के दौरान भी कोई वकील वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी पेश नहीं हुआ। याचिकाकर्ता पुनीत कौर ढांढा के वकील विनीत ढांढा के मुताबिक वो पेश तो हुए थे, लेकिन उनकी आवाज म्यूट थी। ये भी एक रहस्य है कि आवाज म्यूट कैसे हुई? लिस्ट के मुताबिक जब मामला सुनवाई के लिए आया तो मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि पिछली बार भी कोई पेश नहीं हुआ और इस बार भी कोई नहीं! ये क्या हो रहा है? कोर्ट ने टिप्पणी भी की कि हमने पहले भी कहा था कि इस मामले को पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ले जाइए। इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य

न्यायाधीश जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी। याचिका में दिशा की मौत के पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सलियान ने आत्महत्या कर ली थी। दिशा आठ जून की रात में मुंबई की एक बिल्डिंग में 14वीं मंजिल पर मौजूद थीं। दिशा घटना के ठीक पहले मलाड पश्चिम के इलाके की एक बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर अपने होने वाले मंगेतर के साथ थीं। उन्हें पास ही में बोरीवली के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस घटना की छानबीन कर रही है और अभी तक वह किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है कि आखिर सुसाइड की वजह क्या थी। पुलिस चश्मदीद गवाहों के बयान भी दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने दिशा के माता-पिता के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं।

पत्रकारों व इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा: मो .जहांगीर

जरुरत पड़ने पर पूरे देश में आंदोलन छेड़ा जायेगा: राष्ट्रीय महासचिव ईरा

संवाददाता/सैय्यद अल्ताफ हूसैन

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर के जिलाध्यक्ष इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन राजेंद्र गुप्ता पर उनके ही आवास में घुस कर यूपी पुलिस द्वारा जानलेवा हमला किया जाना बहुत ही गंभीर और सोचनीय विषय है एक पुलिस कर्मी वर्दी के रौब में बदमाशों वाला काम कर रहा है पत्रकारों व हमारे संगठन के पदाधिकारियों का इस प्रकार का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा इस प्रकरण को ईरा ने गंभीरता से लिया है और यूपी के राज्यपाल, मुख्यमंत्री,सहित पुलिस महानिदेशक तथा मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा जा रहा है पत्रकार राष्ट्र का चौथा स्तंभ है आज उसका उत्पीड़न किया

जा रहा है अगर शीघ्र ही सरकारें पत्रकार उत्पीड़न पर गंभीर नहीं होती है तो ईरा पुरे देश में आंदोलन छेड़ देगी उक्त विचार इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव मो. जहांगीर ने हमारे संवाददाता से दूरभाष पर वार्ता के दौरान कही श्री खान ने कहा कि पत्रकार उत्पीड़न पर सभी ईरा के प्रदेश अध्यक्षों से चर्चा कर ली गई है शीघ्र ही एसोसिएशन प्रदेशों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर पत्रकार उत्पीड़न पर सख्त कानून बनाये जाने की मांग करेगा कानपुर जिलाध्यक्ष पर पुलिस विभाग का एक अदना सा सिपाही घर में घुस कर हमला कर रहा है ऐसा प्रतीक होता है कि देश प्रदेश में कानून व्यवस्था कुछ बची ही नहीं है और पत्रकार द्वारा स्थानीय थाना में उक्त प्रकरण में तहरीर दी जाती है तो थाना प्रभारी कार्यवाही करने में हीलाहवाली कर रहे हैं जो काफी निंदनीय है राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि शीघ्र ही कानपुर प्रशासन दोषी पुलिस कर्मी पर जानलेवा हमले के तहत मुकदमा दर्ज कर सिपाही को बर्खास्त करने की कार्यवाही करे।

रामपुर हलचल

नगर पालिका परिषद एवं पुलिस के सहयोग के चलते नाले पर किये गये अतिक्रमण को लेकर चलाया गया अभियान

संवाददाता/नदीम अख़्तर

टाण्डा (रामपुर)। नगर पालिका परिषद एवं पुलिस के सहयोग के चलते नाले पर किये गये अतिक्रमण को लेकर चलाया गया अभियान,बाहर रखे सामान आदि को किया गया जब्त, कुछ अतिक्रमण करने वालों से वसूला गया जुमार्ना, नगर के मुख्य मार्ग पर अक्सर दुर्घटना घटित होने का बना रहता है भय, अभियान के चलते दुकानदारों सहित अन्य फड़ वालों में मचा रहा हड़कम्प नगर पालिका परिषद एवं पुलिस के सहयोग के चलते दुकानदारों एवं नाले आदि पर फड़ लगाने वालों को सोमवार के दिन चेतावनी अभियान चलाकर उनको जागरूक किया गया मंगलवार की दोपहर नगर पालिका परिषद एवं पुलिस विभाग के चलते अतिक्रमण अभियान चलाया गया जिसमें दुकानदारों के सामने नाले आदि पर रखे तख्त व अन्य सामान को केटल केचर गाड़ी में भर लिया गया बाकी अन्य अतिक्रमण करने वालों

से जुर्माना भी वसूला गया नालों आदि से अतिक्रमण को हटवाया जा रहा था तभी युवा व्यापार मंडल के मु० सालिम ने सामान आदि हटाये जाने को लेकर अपना विरोध करना शुरू कर दिया जिस पर अधिशासी अधिकारी राजेश सिंह राणा ने कहा कि नगर के मुख्य बाजार के अन्दर दोनों साइडों में नाले मौजूद हैं जिस पर दुकानदारों के सहयोग के चलते उनको पाट दिया गया है अतिक्रमण को साफ कराये जाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है नाले से आगे दोनों तरफ,फल,सब्जी आदि के ढेले लगाकर अपना सामान बेचते हैं ग्राहकों की आवा जा ही होने के कारण भीड़ भाड़ के चलते मार्ग भी अवरूद्ध होकर रह जाता है जिससे दुर्घटना होने की आंशका बनी रहती है अधिशासी अधिकारी ने कहा कि नगर के मुख्य बाजार के अन्दर जहां जहां अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जाता है बीच बीच में अभियान जारी रखा जायेगा इसपर दुकानदार सहित अतिक्रमण करने वालों में हड़कम्प मचा रहा अतिक्रमण करने वालों में अभियान के दौरान ही भय बना रहता है लेकिन अभियान समाप्ती के बाद बाद स्थिति ज्यों की त्यों बनकर रह जाती हैं अभी भी अतिक्रमण कारी अपनी हरकतों से बाज तक नहीं आ पा रहे हैं शासन एवं प्रशासन का जरा भी भय उनके अन्दर अतिक्रमण के दौरान कोतवाल माधो सिंह विष्ट,एस.आई.रामवीर सिंह,एस. आई मनोज कुमार,पंकज चौधरी पुलिस के अलावा अधिशासी अधिकारी राजेश सिंह राणा, डाल चन्द्र, सुदेश,नरेश,फारूक अक्खू, विनोद,पप्पू आदि मुख्य रूप से अन्य सफाई कर्मी मौजूद रहे।

बुलढाणा हलचल

उमेद की महिलाशक्ती का तहसील पर धडक

बुलढाणा। उमेद की महिलाओं ने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान में बाहरी हस्तक्षेप से बचने और काम करने वाले अनुबंध अधिकारियों के पुनः नियोजन को निर्लंबित करने के निर्णय को वापस लेने के लिए 12 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे के बीच तहसील कार्यालय पर धरना दिया। समूहों, ग्राम संघों और वार्ड संघों को दी जाने वाली धनराशि का वितरण किया जाना चाहिए, उम्मेद अभियान में बाहरी व्यवस्था को बंद किया जाना चाहिए, कार्य संसाधन व्यक्तियों का मानदेय तुरंत वितरित किया जाना चाहिए, अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने के संबंध में निर्णय को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। प्रभावित कर्मचारियों को फिर से रोजगार देने की मांग को लेकर उम्मेद जीवनवती अभियान की ओर से शहर में मार्च निकाला गया। दोपहर करीब 1 बजे महिला शक्ति ने तहसील कार्यालय में दस्तक दी और मांगों का विवरण प्रस्तुत किया।इस अवसर पर छया जाधव, नयना जाधव, कीर्ति जाधव, ममता नरोटे, रंजना वानरे सहित कई महिलाएँ उपस्थित थी।

पंजीकृत गरीबों का बकाया भुगतान करें, कामगार कार्यालय पर स्वभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक

बुलढाणा। जिले के मजदूर पिछले कई वर्षों से श्रम कार्यालय में पंजीकरण करा रहे हैं। इन पंजीकृत श्रमिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन जो कर्मी पिछले कई वर्षों से पंजीकृत हैं, उन्हें उनकी अधिकार योजना नहीं मिल रही है। सरकार ने नए पंजीकृत मजदूरों के खाते में कुल 5,000 रुपये, पहले चरण में 2,000 रुपये और दूसरे चरण में 3,000 रुपये जमा किए हैं। लेकिन श्रम कार्यालय के लापरवाह प्रबंधन के कारण, कई लाभार्थी इस योजना से वंचित हैं। कोरोना अवधि के दौरान, सरकार ने श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में योजना की राशि जमा की लेकिन श्रमिकों के कल्याण कार्यालय में कर्मचारी श्रमिकों को अस्पष्ट उत्तर दे रहे हैं। परिणामस्वरूप, पंजीकृत श्रमिकों ने इस गंभीर मामले को स्वाभिमानी के युवा कार्यकारी अध्यक्ष राणा चंदन और अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष शेख रफीक शेख करीम को जानकारी मिली तुरंत राणा चंदन मजदूरों के साथ कामगार कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों और कर्मचारियों को ईस समस्या क हल करने के लिए आक्रामक रुख अपना लिया। स्वाभिमानी अधिकारी राणा चंदन ने कहा कि उनका पंजीकरण तत्काल किया जाना चाहिए। राणा चंदन ने कर्मचारियों के पंजीकरण और बकाया 8 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होने पर सभी कार्यालयों को ध्वस्त करने की कड़ी चेतावनी दी। इस तरह के आक्रामक रुख को देखकर अधिकारियों ने तुरंत योजना को पंजीकृत करना शुरू कर दिया और आश्वासन दिया कि कोई भी मजदूर योजना से वंचित नहीं रहेगा। इसके बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। आंदोलन में संदीप जुगले, हरिभाऊ उबरहंडे, फकीरा निकल्जे, इरफान शाह, मुकेश राजपूत, सैकड़ों मजदूर और जिले के स्वाभिमानी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।

समस्तीपुर हलचल

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा 30 प्रवाषि को प्रक्षिशित किया जा रहा है

समस्तीपुर/कल्याणपुर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) योजना अंतर्गत अनमोल उपहार सेवा फाउंडेशन द्वारा अन्नपूर्णा विद्या मंदिर, कल्याणपुर में 30 प्रवासी एवं जरूरतमंद अकुशल मजदूरों के लिए 16 सितंबर से चलाए जा रहे तीस दिवसीय पलम्बर प्रशिक्षण कार्यक्रम का 22 वां दिन मंगलवार को औचक निरीक्षण डीडीएम नाबार्ड जयंत विष्णु ने किया। डीडीएम श्री विष्णु ने प्रशिक्षणार्थी से रू-ब-रू होते हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपलोग लगन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा अपना एक बेहतर व्यक्तित्व विकसित करें जिससे आपकी पहुंच बढ़ेगी और काम का दायरा भी बढ़ेगा। प्रशिक्षणार्थी विश्व रंजन कुमार, विवेक कुमार, जितेन्द्र झा, पप्पु पंडित, बूटन पंडित, विपिन कुमार, कमलेश राय, विपिन कुमार, विनोद कुमार शर्मा आदि ने बताया कि हमलोग मोटर से टंकी में पानी पहुंचाना तथा टंकी से पानी निचे उतारना, नल लगाना, हिंदी तथा इंग्लिश सीट का फिटिंग करना, पाईप वायरिंग करना, शौचालय की चैन, स्नानघर में कनेक्शन करना, सावर लगाना आदि सीख गये हैं। कमलेश राय ने कहा कि इस कोरोना काल में नाबार्ड एवं औसेफा हमलोगों के लिए वरदान साबित हुई है। मौके पर औसेफा के निदेशक देव कुमार, कोर्डिनेटर मनोज कुमार, मास्टर ट्रेनर नवीन कुमार, ट्रेनर राम कुमार ठाकुर आदि थे।

हॉट सीट माने जाने वाले हसनपुर में होगा दिलचस्प चुनाव, तेजप्रताप ने हसनपुर सीट से किया नामांकन

संवाददाता/जेड अहमद

समस्तीपुर। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 140 से आज लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने नामांकन दाखिल किया। इनके साथ नेता प्रतिपक्ष और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। तेजस्वी ने कहा कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनना तय है। बिहार के तमाम बेरोजगार युवाओं, दलित, गरीब, गुरबों ने इसके लिए कमर कस ली है। वहीं उजियारपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शील कुमार राय ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर से बीजेपी सांसद नित्यानन्द राय भी मौजूद रहे। नित्यानन्द राय ने कहा कि 2020 में 220 यही एनडीए का नारा है और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। समस्तीपुर जिले के सभी 10 विधानसभा सीट पर नित्यानंद राय ने एनडीए उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास के मुद्दे पर ही यह चुनाव हो रहा है। महागठबंधन का इस बार नॉमिनेशन नहीं बचने जा रहा है। बता दें कि इससे पहले तेजप्रताप वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते थे।

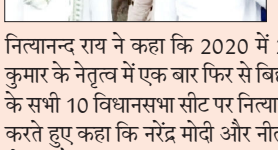

कल्याणपुर पुलिस को मिली सफलता, अपराध की योजना बनाते पांच गिरफ्तार, हथियार बरामद

समस्तीपुर/कल्याणपुर। सदर डी एस पी प्रीतीश कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि कल्याणपुर थाना की पुलिस ने अपराध की योजना बनाते पांच अपराधियों को किया गिरफतार किया है। कल्याणपुर थाना की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कुछ अपराधी लदौरा बांध किनारे अपराध की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने अपने दलबल के साथ उसका पीछा कर लदौरा बांध किनारे से पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से दो पिस्तौल, तीन ज़िंदा कारतूस बरामद किया गया है। वहीं तीन मोटसाइकिल भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में बिट्ठु कुमार, सुधांशु कुमार, राकेश कुमार, दीपक कुमार, सोनू कुमार सभी कल्याणपुर थाना क्षेत्र के ही निवासी है। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने कई मामले का खुलासा किया,वहीं और भी कई मामलों का उद्भेदन होने की संभावना है।वहीं इनकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध में कमी आयेगी।

बुलढाणा जिले में मिले 25 नए संक्रमित

बुलढाणा। जिले में मंगल को और नए 25 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं 91 मरीज कोरोना मुक्त होने के कारण उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। जिले में रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आने से जिला वासीयों ने राहत की सांस ली है। मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार रैपिड एंटीजन टेस्ट किट द्वारा और परीक्षण के लिए प्रयोगशाला को भेजी गई रिर्पोटों से कुल 245 प्राप्त हुई है। इनमें से 220 रिर्पोट कोरोना नेगेटिव और 25 रिपोर्ट पॉजिटिव थीं। प्राप्त सकारात्मक रिपोर्ट में 23 प्रयोगशाला रिपोर्ट और 2 रैपिड टेस्ट रिपोर्ट शामिल हैं। नकारात्मक रिपोर्ट में प्रयोगशाला से 157 रिपोर्ट और रैपिड टेस्ट से 63 रिपोर्ट शामिल हैं। इस प्रकार 220 रिपोर्ट नकारात्मक पाए गए हैं। साथ ही आज तक 34786 रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। इसी तरह अब तक 7594 कोरोना संक्रमित मरीजों को नीगेटीव रिपोर्ट आने पर मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुसार डिस्चार्ज किया गया है। आज, 262 नमूने रिपोर्ट का इंतजार में हैं।

आराम भी है जरूरी, 6 घंटे से कम सोने पर हो सकती है यह बीमारी

सारा दिन काम करने के बाद रात के समय आराम करना बहुत जरूरी है। जिससे थकावट उतर जाए और अगले दिन के लिए फिर एनर्जी भर जाए। हाल ही में हुए एक शोध से यह बात सामने आई है कि जो लोग दिन में 6 घंटे से कम सोते हैं उन्हे किडनी की बीमारी होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इस बीमारी को सीकेडी कहते हैं। इसके साथ-साथ ब्लड प्रैशर,मोटापा और डायबिटीज होने का भी डर रहता है। अगर शरीर में इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो जल्द ही डॉक्टरी जांच करवाएं और अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं।

क्या है सीकेड

इसका अर्थ है गुर्दे के काम करने की क्षमता में कमी होना। यह स्थिति बिगड जाने पर कीडनी फेल होने का खतरा रहता है। गुर्दे का काम है शरीर से बेकार पर्दाथों को बाहर निकालना लेकिन जब कीडनी में खून का प्रवाह प्रभावित होता है तो यह अच्छे से काम नहीं कर पाती और बीमारियों को जन्म देती हैं। इसके साथ शरीर सेहत से जुड़ी कई तरह की बीमारियों से घिरना शुरू हो जाता है।

इस तरह करें बचाव

लाइफस्टाइल में बदलाव करके खुद को स्वस्थ रखें। पर्याप्त भोजन करें और नींद भी पूरी लें। इसके साथ ही इन बातों का भी खाल ख्याल रखें।

1. फिट रहने के लिए पूरा आराम करें और इसके साथ ही एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालें। इससे रक्तचाप भी सामान्य रहेगा।
2. डायबिटीज पर कंट्रोल रखें। खाने में मीठे से पूरा परहेज करें।
3. वजन लगातार कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो समय पर डॉक्टरी जांच जरूर करवाएं।

सिजेरियन के बाद सी-सेक्शन के निशान को ऐसे करें गायब

जिन महिलाओं की डिलवरी सी-सेक्शन यानी सिजेरियन के जरिए होती है उन्हें अधिक केयर की जरूरत होती है। क्योंकि उस महिला का शरीर काफी कमजोर हो गया होता है जिसको रिपेयर होने में काफी समय लगता है। वहीं सी-सेक्शन का निशान भी काफी परेशान करता है, जिस वजह से साड़ी पहनना मुश्किल हो जाता है। इस निशान को कम करने के लिए महिलाएं बहुत से तरीके तो अपनाती है लेकिन निशान गायब नहीं हो पाता है। अगर आप भी सी-सेक्शन के निशान के परेशान है तो हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिससे निशान काफी लाइट हो जाएगा।

- नींबू और शहद

नींबू के रस में शहद मिलाएं। फिर इस पेस्ट को सी-सेक्शन के निशान पर लगाएं इससे निशान लाइट हो जाएगा। नींबू दाग को गायब करने का काम करता है, वहीं शहद त्वचा को साफ कर उसमें नमी प्रदान करता है।

- टी ट्री और लेवेंडर ऑयल

इन दोनों तेल को मिलाकर सी-सेक्सन के निशान पर मसाज करें इससे वहां का सकुर्लेशन तेज होगा और घाव के निशान कम हो जाएगा। इस प्रकिया को दिन में एक बार करें।

- एलोवेरा जेल

एलोवेरा भी निशान को गायब कर देता है लेकिन याद रखें कि नैचुरल एलोवेरा जैल का इस्तेमाल करें। दिन में 2 बार एलोवेरा जैल को निसान पर लगाएं। इससे निशान लाइट हो जाएगा और उसमें होंने वाली जलन भी कम होंगी।

- कोकोआ बटर

कोकोआ बटर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ऑपरेशन के निशान को कम करने का काम करता है। निशान पर कोकोआ बटर लगाएं। इससे निशान भी लाइट होता है और वहां नमी बनी रहती है।

इन 6 होममेड टिप्स से बनाएं बालो को लंबा और खुबसूरत

आजकल लड़कियां लंबे बालों के साथ तरह -तरह के हेयर स्टाइल रखना पंसद करती है। अलग तरह के हेयर स्टाइल बनाते-बनाते बाल रफ हो जाते है। ऐसे में आपके बाल खराब दिखने लगते है। आज हम आपको बालों को स्वस्थ और मजबूत रखने के कुछ टिप्स बताएंगे। इससे बार-बार हेयर स्टाइल बनाने पर भी आपके बाल खराब नहीं होंगे।

1. मालिश करना

हफ्ते में दो बार गर्म तेल से बालों में मालिश करने पर बालों का झड़ना बंद हो जाता है। इसके अलावा ऐसा करने से आपके बाले चमकदार भी होते है। इसलिए बालों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से मालिश जरूर करें।

2. पोषक तत्व

ज्यादा से ज्यादा खनीज और प्रोटीन्स आहारों का सेवन करने से बालों को ज्यादा समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। पौष्टिक आहार का सेवन आपके बालों को बिना किसी नुकसान के अच्छी ग्रोथ देने में मदद करता है।

3. गीले बाल

एकेसर आप गीले बालों में कंधी मारने लग जाते है। इससे आपके बाल जल्दी खराब हो जाते है। इसके अलावा बाल धोने के बाद उसे ज्यादा देर तक तोलिए में लपेट कर रखने से भी बाल खराब हो जाते है।

4. होममेड शैम्पू

एक खाली बोतल या गिलास में 4 oz पानी डाल कर उसमें 4 ङ्क्ष् लिक्वट कैस्ट्रॉल साबुन डाल कर अच्छी तरह से घोल लें। अब आप इसमें रोज ऑयल या लैवेंडर ऑयल डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप इसे शैम्पू की तरह इस्तेमाल कर सकते है।

5. होममेड कंडीशनर

होममेड कंडीशनर बनाने के लिए 4 टेबलस्पून ऐलोवेला, 1 नींबू और 4 ड्रोप पुदीने के तेल को अच्छी तरह मिला कर बाल को शेम्पू करने के बाद लगा लें। करीब 5 मिनट बाद बालों को ठंडे पानी से धे लें।

6. बालों को ट्रिम करवाना

समय-समय पर बालों को ट्रिम करवाने से वो ज्यादा लंबे और स्वस्थ रहते है। इससे आपके बालों में से खराब बाल निकल जाते है। आप चाहें तो घर पर खुद भी बालों को ट्रिम कर सकती है।

ब्रश करने पर मसूढ़ों से निकलता है खून तो आजमाएं ये नुस्खे

कई बार ब्रश करते या कुछ खाते समय मसूढ़ों में से खून आने लगता है और इनमें सूजन भी हो जाती है जिसे पायरिया भी कहते हैं। इस समस्या को लोग मामूली मानकर अनदेखा कर देते हैं लेकिन जब हर बार कोई सख्त चीज खाने पर मसूढ़ों में से खून निकले तो इससे आगे चलकर दांतों की कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है। ऐसे में इसका तुरंत इलाज करवाना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय करके भी मसूढ़ों में से आने वाले खून को रोका जा सकता है। आइए जानिए इसके लिए क्या किया जाए।

1. सेंधा नमक

पायरिया की समस्या होने पर सेंधा नमक में सरसों का तेल मिलाकर पतला लेप बना लें। अब उंगली की मदद से इस लेप को मसूढ़ों पर लगाएं और हल्की मसाज करें। रोजाना दिन में 2 बार इस लेप से मालिश करने से कुछ ही दिनों में मसूढ़ों की सूजन और खून आना बंद हो जाएगा।

2. हल्दी

इसके लिए हल्दी में सरसों का तेल मिलाकर पेस्ट बनाएं। रात को सोने से पहले इससे मसूढ़ों की मालिश करें। कुछ दिनों तक लगातार इसका इस्तेमाल करने से खून आना बंद हो जाएगा और मसूढ़ों में होने वाली दर्द भी दूर होगी।

3. कपूर

कपूर को पीसकर उसमें अरंडी का तेल मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इसे मसूढ़ों पर कुछ देर के लिए लगा कर रखें जिससे खून आना बंद हो जाएगा।

4. संतरे के छिलके

इसके लिए संतरे के छिलकों को पीसकर उसका पाउडर बना लें। इस पाउडर को मंजन की तरह इस्तेमाल करें। सुबह-शाम इसका इस्तेमाल करने से पायरिया की समस्या से राहत मिलेगी।

5. शहद

मसूढ़ों में से खून आने पर शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आधा चम्मच शहद में 2 बूंदे नींबू का रस मिलाएं और इससे मसूढ़ों पर लगाकर रखने से फायदा होगा।

दैनिक मुंबई हलचल
अब हर सच होगा उजागर

ऋतिक संग नाम जोड़े जाने पर बोलीं उर्वशी

एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, लेकिन गुजरे 3-4 महीने उनके लिए काफी तनावपूर्ण रहे हैं। इसपर बात करते हुए उर्वशी कहती हैं, सोशल मीडिया स्पेस में बहुत नकारात्मकता है, जिसने मुझे मानसिक रूप से मुझे प्रभावित किया है। उर्वशी ने कहा, मुझ पर कई झूठे आरोप लगे थे कि मैं रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक ऋतिक रोशन से फोन पर बात किया करती थी। इन झूठे आरोपों से सेलिब्रिटीज को नुकसान होता है, चाहे वह स्टार किड हो या एक बाहरी व्यक्ति। महत्वपूर्ण बात जो मैंने नोटिस की वह यह है कि इस तरह की कहानियां स्टार किड्स के लिए कभी नहीं होती हैं। मैं ऋतिक और उनके काम की प्रशंसक हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे पास उनके लिए एक प्यार का एंगल है। ये चीजें मानसिक स्वास्थ्य वाले लोग को प्रभावित करती हैं और शायद सुशांत के साथ भी यहीं हुआ होगा।

क्या रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जल्द कर रहे हैं शादी?

नीतू कपूर का कुछ दिनों पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह डांस रिहर्सल कर रही थीं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कहा जा रहा था कि कहीं नीतू, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तैयारी तो नहीं कर रहीं। आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। खबर के मुताबिक कपूर परिवार के एक सदस्य ने इन खबरों को गलत बताया है। उनका कहना है कि ना तो इस साल और ना ही अगले साल शादी होने वाली है। ऋषि कपूर का निधन अप्रैल में हुआ था तो 2021 के बीच तक शादी का सवाल ही नहीं खड़ा हो सकता जब तक की रणबीर और आलिया खुद शादी नहीं करना चाहते हो। वैसे भी रणबीर की मां को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी रणबीर और आलिया खुद शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान आलिया ने बताया था कि वह रणबीर के साथ अपने रिश्ते को दोस्ती के रूप में देखना पसंद करती हैं। आलिया ने कहा था, यह एक रिश्ता नहीं है। यह एक दोस्ती है। मैं इस बात को पूरी ईमानदारी के साथ कह रही हूं। यह खूबसूरत है। मैं अभी सितारों और बादलों पर चल रही हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम दो व्यक्ति हैं, जो अभी अपनी-अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यह ऐसी स्थिति नहीं है जहां आप हमें लगातार एक साथ देखेंगे। यह एक कम्फर्टेबल रिलेशन की असली निशानी है। नजर ना लगे। वास्तव में रणबीर मेरे शानदार दोस्त हैं।

'अतरंगी रे' के लिए अक्षय कुमार को मिली भारी भरकम फीस?

यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि अक्षय कुमार बॉलिवुड के सबसे व्यस्त ऐक्टर्स में से एक हैं। अक्षय ने हाल ही में अपनी फिल्म 'बेल बॉटम' की शूटिंग खत्म की है और वह इसके बाद तुरंत बाद अपनी अगली फिल्म की शूटिंग में लग चुके हैं। इस वक्त अक्षय अपनी अगली फिल्म 'अतरंगी रे' की भारी भरकम फीस को लेकर चर्चा में हैं। अक्षय कुमार आनंद एल. रॉय की फिल्म 'अतरंगी रे' में भी नजर आनेवाले हैं, जिसमें उनके साथ नजर आएंगी सारा अली खान। फिल्म में इन दोनों स्टार्स के अलावा साउथ सिनेमा के स्टार धनुष भी हैं। अब खबर है कि अक्षय ने अपनी इस फिल्म के लिए काफी बड़ा अमाउंट चार्ज किया है। खबर के मुताबिक, इस फिल्म के लिए उन्हें 27 करोड़ रुपये मिलने वाला है और वह दो वीक की शूटिंग करेंगे। सोर्स के मुताबिक, आमतया वह अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरा एक दिन के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन राय की फिल्म अतरंगी के लिए उन्हें ऑलमोस्ट डबल पैसे दिए गए हैं।